

DISH DOCTOR



Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing, 3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or

Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

STANDARDS OF QUALITY OF SERVICE

Q: What are the key regulatory changes, monitoring frameworks, and benchmark standards introduced under TRAI's Standards of Quality of Service of Access (Wireline and Wireless) and Broadband (Wireline and Wireless) Service Regulations, 2024?

Sudipto Dey, Kolkata

Ans.: Notified by the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) and effective October 1, 2024, the unified framework supersedes older standalone regulations from 2006, 2009, and 2012. It establishes a single regulatory standard across 2G, 3G, 4G, 5G, and wireline fiber networks to address technology convergence and emerging application demands.

KEY REGULATORY MANDATES & BENCHMARK STANDARDS

- ◆ **Tightened Network Benchmarks:** Aligned with global standards, introducing stricter thresholds for latency and new parameters for jitter and packet drop rates (uplink/downlink) to support high-speed broadband and real-time 5G applications. Stricter cumulative downtime limits and worst-affected cell thresholds enforced in a graded manner over six to thirty months.
- ◆ **Granular Monitoring & Frequency Shift:** QoS parameters such as network availability, call drops, and voice packet drop rates are monitored at the individual cell level rather than macro-averaged service areas.
- ◆ **Consumer Transparency & System Upgrades: Geospatial:** Operators must display technology-wise (2G/3G/4G/5G) coverage maps on their websites. Service providers must publish monthly QoS compliance reports online using automated, direct system monitoring.
- ◆ **Compliance & Disincentives:** Introduces graded financial disincentives that escalate with continuous non-compliance. ■

सेवा की क्वालिटी के मानक

प्रश्नः ट्राई के 'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सर्विस रेगुलेशन, 2024 के तहत सर्विस की क्वालिटी के लिए कौन से मुख्य रेगुलेटरी बदलाव, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और बेंचमार्क स्टैंडर्ड लागू किये गये हैं?

सुदीप्तो डे, कोलकाता

उत्तरः टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) द्वारा अधिसूचित किया गया और 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाला यह यूनिफाइड फ्रेमवर्क 2006, 2009 और 2012 के पुराने अलग-अलग नियमों की जगह लेगा। यह तकनीकी के एकसाथ आने (कन्वर्जेंस) और नये आवेदनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2जी, 3जी, 4जी, 5जी और वायरलाइन फाइबर नेटवर्क के लिए एक ही रेगुलेटरी स्टैंडर्ड बनाता है।

मुख्य रेगुलेटरी नियम और बेंचमार्क स्टैंडर्ड

- ◆ **नेटवर्क बेंचमार्क को कठोर करना:** वैश्विक मानक के मुताबिक, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और रीयल टाइम 5जी आवेदन को सपोर्ट करने के लिए लेटेंसी के लिए सख्त लिमिट और ज़िटर और पैकेट ड्रॉप रेट (अपलिक/डाउनलिक) के लिए नये पैरामीटर लागू किये जा रहे हैं। कुल डाउन टाइम की सख्त लिमिट और सबसे ज्यादा प्रभावित सेल के लिए लिमिट को छह से तीस महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।
- ◆ **बारीकी से निगरानी और फ्रीक्वेंसी में बदलाव:** क्यूओएस पैरामीटर जैसे नेटवर्क की उपलब्धता, कॉल ड्रॉप और वॉइस पैकेट ड्रॉप रेट की निगरानी मैक्रो-औसत सर्विस एरिया के बजाय अलग-अलग सेल लेवल पर की जाती है।
- ◆ **उपभोक्ता पारदर्शिता और सिस्टम अपग्रेड:** जियोस्पेशियल ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर तकनीकी के हिसाब से (2जी/3जी/4जी/5जी) कवरेज मैप दिखाने होंगे। सेवा प्रदायकों को ऑटोमेटेड, डायरेक्ट सिस्टम मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करके हर महीने क्यूओएस कंप्लायंस रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित करनी होंगी।
- ◆ **अनुपालन और दंड:** इसमें श्रेणीबद्ध वित्तीय दंड का प्रावधान है, जो लगातार नियमों का पालन न करने पर बढ़ते जाते हैं। ■